



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, बुधवार, 27 दिसम्बर, 2006/6 पौष, 1928

---

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 27 दिसम्बर, 2006

संख्या वि०स०-विधायन-गवर्नमेंट बिल०/1-60/2006.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अभिधृति और

भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक-30) जो आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2006 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गाज़टा,  
सचिव ।

## हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2006 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 15 मई, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 में,— धारा 118 का संशोधन।

(क) उप-धारा (2) के खण्ड (छ) में, "हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश राज्य आवास बोर्ड," शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर "हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे; और

(ख) उप धारा (3-क) के खण्ड (ख) में अंकों और शब्द "90 दिन" के स्थान पर "छह मास" शब्द रखे जाएंगे।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 को निरसित कर हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 के अधिनियमित किए जाने पर हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के स्थान पर हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश अभिवृद्धि और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के अधीन हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड गैर-कृषक को घरों या दुकानों के निर्माण के लिए भूमि के अन्तरण या बने बनाए गृहों या दुकानों के अन्तरण के लिए सशक्त है। अब उक्त नए अधिनियम के अधीन हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश अभिवृद्धि और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 में पारिणामिक संशोधन किया जाना भी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में आया है कि धारा 118 की उप धारा (3-क) में कलक्टर द्वारा, इस धारा के उल्लंघन में किसी भूमि के अन्तरण से सम्बन्धित किसी निर्देश पर विनिश्चय लेने के लिए दी गई नब्बे दिन की अवधि युक्तियुक्त नहीं है। इसलिए उक्त अवधि को छह मास तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

सत महाजन,  
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :  
तारीख....., 2006.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

— शून्य—



# THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS (AMENDMENT) BILL, 2006

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

## BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (Act No. 8 of 1974).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

Short title  
and  
commence-  
ment.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Act, 2006.

(2) Save as otherwise provided in this Act, clause (a) of section 2 shall be deemed to have come into force on the 15<sup>th</sup> day of May, 2004.

Amendment  
of section  
118.

2. In section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972, —

- (a) In sub-section (2), in clause (g), for the words, signs and figures, “Himachal Pradesh State Housing Board, established under the Himachal Pradesh Housing Board Act, 1972”, the words, signs and figures, “Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority, established under the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004” shall be substituted; and
- (b) in sub-section (3-A), in clause (b), for the figures and word “90 days”, the words “six months” shall be substituted.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

With the enactment of the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004, by repealing Himachal Pradesh Housing Board Act, 1972, the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority has been established in place of Himachal Pradesh Housing Board.

Under section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972, the Himachal Pradesh Housing Board established under the Himachal Pradesh Housing Board Act, 1972, is empowered to transfer land for construction of houses or shops, or to transfer built up houses or shops to non-agriculturist. Now, with the establishment of the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority under the said new Act, consequential amendment is also required in section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972. Further, it has also been observed that period of 90 days provided in sub-section (3-A) of section 118, for taking decision by the Collector on any reference regarding transfer of any land in contravention of this section is not reasonable. Hence, it has been decided to enhance the said period up to six months. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the above objectives.

**SAT MAHAJAN,**  
*Minister-in-charge.*

SHIMLA :

Dated the....., 2006.

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

Nil

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Nil

